

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6113
जिसका उत्तर बुधवार, 4 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों की रिहाई

6113. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचाराधीन कैदियों की रिहाई में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ;

(ख) यदि हां, तो विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सिफारिशों से जेल में पड़े 2.38 लाख विचाराधीन कैदियों की रिहाई में कितनी सहायता मिलने वाली है ;

(घ) क्या विधि आयोग ने इस संबंध में मेराजस्थान बनाम बालचंद के उच्चतम न्यायालय के 40 वर्ष पूर्व के निर्णय को उद्धृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विधि आयोग की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।
